



न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

नजरसानी प्रकरण सं0 11/2018

1. हरभजन कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 3 आर.बी. तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत
2. विकास अधिकारी , पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. गेजा सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर
4. सुबेग सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर

अप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. आदेश दिनांक 10.11.1986 को आवंटन खारिज कर अहाता संख्या 140 अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को दिनांक 20.03.1991 आवंटन किया गया, को निरस्त कर आवंटन 06.08.1983 बहाल किये जाने बाबत।

उपस्थित :-

1. श्री तेजा सिंह अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री सुरेश अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. श्री सुभाष मिठा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 व 4

आदेश

दिनांक: 28.05.2018

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि " आदेश अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 3 आर.बी. दिनांक 10.11.1986 को खारिज कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 व 04 को आवंटन करना खिलाफ कानून, वाक्यात व इन्साफ न होने की वजह से काबिले खारिजी है। जिला कलक्टर को एक शिकायत प्रस्तुत की गयी कि ग्राम पंचायत 3 आर.बी. के 26 व्यक्तियों को 37 आर.बी. में विधि विरुद्ध अहाते अलॉट किये गये है जिसकी जांच कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे। जिला कलक्टर द्वारा पंचायत विभाग के पंचायत प्रसार अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया गया , पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रार्थीया के पति के नाम से आवंटन अहाता नम्बर 140 के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट की गयी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अहातों को खारिज करने के लिए निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जो पत्रावली में 13.02.1985 लगाये गये आक्षेपों के आधार पर प्रशासन स्थाई समिति द्वारा निलामी को स्वीकृत नहीं करने का सहारा लेकर अस्वीकृत कर दिया और इस आधार पर दिनांक 10.11.1986 को संचिव ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए को उक्त कागजों में निरस्त कर कार्यालय में पालना प्रस्तुत करने हेतु लिख दिया गया। इसके आधार पर सचिव ने दिनांक 10.11.1986 को प्रार्थीया के पति का आवंटन खारिज कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 को आवंटन करने का आदेश दिया है, जो बिना पत्रावली तैयार किया गया

**अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर**



है। प्रार्थीया के पति का आवंटन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अगर जांच में अनियमितता पायी जाती है तो पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 27(ए) में व पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 272 में निगरानी प्रस्तुत कर भी आवंटन खारिज करवाया जा सकता है अन्यथा नहीं ? अधीनस्थ अदालत ने विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है व रेस्पोजेन्ट को रकबा अलॉटमेंट किया है। उक्त आवंटन करने से पूर्व निलामीकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण काबिले निरस्ती है। उक्त अहाते से सम्बन्धित रिकॉर्ड में दिनांक 10.11.1986 को खसरा रजिस्टर प्रार्थीया के पति के नाम से आवंटन खारिज का नोट अंकित व रेस्पोजेन्ट संख्या 03 व 04 के नाम से आवंटन दर्ज करने का नोट लगा है, लेकिन इसकी कोई मिसल नहीं है, कोई कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव नहीं है, कब प्रार्थना-पत्र दिया, कब पत्रावली बनी, कब निलामी हुई। ऐसा कोई रिकॉर्ड पंचायत रिकॉर्ड के अन्तर्गत नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीया ने नकल के लिए आवेदन पत्र भी दिया कि इस सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड नहीं है रिकॉर्ड गंगानगर भेजा हुआ है। श्रीगंगानगर में प्रार्थीया ने दिनांक 26.03.2018 को नकल के लिए आवेदन पत्र दिया लेकिन उसमें भी केवल खसरा रजिस्टर में ही नोट अंकित है पत्रावली नहीं है। इस कारण रेस्पोजेन्ट आवंटन आदेश पेश करने में असमर्थ है। खसरा रजिस्टर को ही नकल मानकर निगरानी दर्ज की जानी इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोजेन्ट नम्बर 03 व 04 को आवंटन कर दिया जबकि इन्ही रेस्पोजेन्ट नम्बर 03 व 04 को अहाता नम्बर 75, 81, 145,147,154 आवंटन करवाया था जिसकी सामूहिक रूप से जांच की गयी और जांच में इनको पात्र नहीं मानते हुए इनके अलॉटमेंट खारिज किये हैं तो दोबारा इनको नया आवंटन नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.11.1986 एकतरफा है। जिसका ज्ञान प्रार्थीया को इससे पूर्व नहीं था। वकील के बताने पर दिनांक 25.03.2018 को ईल्म हुआ। ईल्म होते ही नकल के लिए पंचायत 3 आर.बी.ए में आवेदन पत्र दिया गया। नकल प्राप्त नहीं हुई अदालत में जो निगरानी चल रही है उसमें आवेदन पत्र दिया उसमें खसरा रजिस्टर की नकल दिनांक 28.03.2018 को प्राप्त हुई है। नकल प्राप्त होते ही आज बिना किसी देरी व लापरवाही के अन्दर अवधि निगरानी पेश की जा रही है। इसलिए निगरानी पेश करने में हुई देरी कन्डोन की जानी इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश 10.11.1986 व रेस्पोजेन्ट का आवंटन निरस्त कर निगरानीकर्ता का आवंटन बहाल करने का आदेश प्रदान करें।

निगरानी से संबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि, " आदेश अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 3 आर.बी. दिनांक 10.11.1986 को खारिज कर रेस्पोजेन्ट संख्या 03 व 04 को आवंटन करना खिलाफ कानून, वाक्यात व इन्साफ न होने की वजह से काबिले खारिजी है। जिला कलक्टर में एक शिकायत प्रस्तुत की गयी जो कि ग्राम पंचायत 3 आर.बी. के 26 व्यक्तियों को 37 आर.बी. में विधि विरुद्ध अहाते अलॉट किये गये



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

है जिसकी जांच कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे। जिला कलक्टर द्वारा पंचायत विभाग के पंचायत प्रसार अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया गया, पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रार्थीया के पति के नाम से आवंटन अहाता नम्बर 140 के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट की गयी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अहातों को खारिज करने के लिए निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जो पत्रावली में 13.02.1985 लगाये गये आक्षेपों के आधार पर प्रशासन स्थाई समिति द्वारा निलामी को स्वीकृत नहीं करने का सहारा लेकर अस्वीकृत कर दिया और इस आधार पर दिनांक 10.11.1986 को सचिव ग्राम पंचायत 3 आरबीए को उक्त कागजों में निरस्त कर कार्यालय में पालना प्रस्तुत करने हेतु लिख दिया गया। इसके आधार पर सचिव ने दिनांक 10.11.1986 को प्रार्थीया के पति का आवंटन खारिज कर रेस्पोजेन्ट संख्या 3 व 4 को आवंटन करने का आदेश दिया है, जो बिना पत्रावली तैयार किया गया है। प्रार्थीया के पति का आवंटन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अगर जांच में अनियमितता पायी जाती है तो पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 27(ए) में व पंचायत अधिनियम 1961 के नियम 272 में निगरानी प्रस्तुत कर भी आवंटन खारिज करवाया जा सकता है अन्यथा नहीं? अधीनस्थ अदालत ने विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जो अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर आदेश पारित किया है व रेस्पोजेन्ट को रकबा अलॉटमेन्ट किया है। उक्त आवंटन करने से पूर्व निलामीकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण काबिले निरस्ती है। उक्त अहाते से सम्बन्धित रिकॉर्ड में दिनांक 10.11.1986 को खसरा रजिस्टर प्रार्थीया के पति के नाम से आवंटन खारिज का नोट अंकित व रेस्पोजेन्ट संख्या 03 व 04 के नाम से आवंटन दर्ज करने का नोट लगा है, लेकिन इसकी कोई मिसल नहीं है, कोई कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव नहीं है, कब प्रार्थना-पत्र दिया, कब पत्रावली बनी, कब निलामी हुई। ऐसा कोई रिकॉर्ड पंचायत रिकॉर्ड के अन्तर्गत नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीया ने नकल के लिए आवेदन पत्र भी दिया कि इस सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड नहीं है रिकॉर्ड गंगानगर भेजा हुआ है। श्रीगंगानगर में प्रार्थीया ने दिनांक 26.03.2018 को नकल के लिए आवेदन पत्र दिया लेकिन उसमें भी केवल खसरा रजिस्टर में ही नोट अंकित है पत्रावली नहीं है। इस कारण रेस्पोजेन्ट आवंटन आदेश पेश करने में असमर्थ है। खसरा रजिस्टर को ही नकल मानकर निगरानी दर्ज की जानी इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोजेन्ट नम्बर 03 व 04 को आवंटन कर दिया जबकि इन्ही रेस्पोजेन्ट नम्बर 03 व 04 को अहाता नम्बर 75, 81, 145,147,154 आवंटन करवाया था जिसकी सामूहिक रूप से जांच की गयी और जांच में इनको पात्र नहीं मानते हुए इनके अलॉटमेन्ट खारिज किये है तो दोबारा इनको नया आवंटन नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.11.1986 एकतरफा है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश 10.11.1986 व रेस्पोजेन्ट का आवंटन निरस्त कर निगरानीकर्ता का आवंटन बहाल करने का आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा जिन भूखण्डों के सम्बन्ध में निगरानी पट्टा निरस्त करने हेतु



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत की है उसमें तमाम कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा की गई थी तथा तमाम तथ्य निरीक्षण दल तथा ग्राम सचिव के समक्ष रखे गये थे जिनके आधार पर पूर्व सरपंच द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर लगभग 29 पट्टे एक ही परिवार के सदस्यों के नाम से जारी कर दिये गये थे। उनमें से भूखण्ड संख्या 140 के सम्बन्ध में निगरानी पेश की गई है तथा तथ्यों को छिपाते हुए कार्यवाही की जा रही है। भूखण्ड संख्या 140 जो निरस्त किया गया वह विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर निरस्त किया गया है। अहाता संख्या 140 को दिनांक 20.03.1991 को विधिवत पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर दो अन्य अहातों के साथ अधिकतम बोली रूपये 1500/- दी जाकर आवंटन हुआ है। दौराने बहस आवंटन से सम्बन्धित पत्रावली की फोटो प्रति अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने पेश की है। इस प्रकार निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त निगरानी भूखण्ड वाके चक 37 आरबीए के अहाता संख्या 140 के सम्बन्ध में दिनांक 12.04.2018 को प्रस्तुत की है और इसी भूखण्ड के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने एक वाद अनवानी परमिन्द्र सिंह वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान अदालत -सिविल न्यायधीश (क.ख.) श्रीगंगानगर के समक्ष वाद संख्या 47/14 दिनांक 01.10.2014 को प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। आदेश दिनांक 10.11.1986 ग्राम पंचायत का नहीं होकर पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा किये गए निर्णय के आधार पर विकास अधिकारी पदमपुर द्वारा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में यह कहीं अंकित नहीं किया कि निगरानीधीन आदेश का ज्ञान निगरानीकर्ता को कब व किससे हुआ। यह समस्त तथ्य निगरानीकर्ता द्वारा मात्र इस आवेदन पत्र को रंग देने के लिए झूठे व मनघण्डत अंकित किए गए हैं, जबकि निगरानीधीन आदेश का ज्ञान शुरू से ही निगरानीकर्ता को है क्योंकि विकास अधिकारी पदमपुर द्वारा बाद प्रशासनिक जांच निगरानीकर्ता व इस चक के अन्य कई परिवारों के पट्टे दिनांक 10.11.1986 को निरस्त कर दिए हैं। इनकी तार्जद "बीडीओ पदमपुर का उक्त वाद में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दिनांक 27.11.2014 के अनुसार गांव 37 आर.बी. का अहाता संख्या 135 ता 143 ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए के पास उपलब्ध खसरा रजिस्टर के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 में लिये गये निर्णय अनुसार निरस्त किये गये हैं " होती है इसके उपरान्त उक्त अहाताजात को गांव के अन्य निवासियों को अलाट कर दिए गए तथा आवंटन के पश्चात आवंटित व्यक्ति अपने-अपने अहाताजात पर काबिज चले आ रहे हैं। अहाता संख्या 140 बाद में अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी 30 वर्षों के बाद पेश की गई है जिसमें हुई देरी का कोई स्पष्ट कारण भी अपने आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया है। लिहाजा निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा 24.06.1983 को निलामी आम में निगरानीकर्ता की बोली अहाता नम्बर 140 के लिए सबसे अधिक 200 रूपये होने के कारण निगरानीकर्ता को बोली में दिये गये हैं जिनका पट्टा दिनांक 05.08.1986 को जारी किया गया



अति.मिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जबकि ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये मूल अभिलेख के तहत उपलब्ध करवाई गई पत्रावलियों को देखने पर पाया गया कि प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 द्वारा उक्त निलामी अस्वीकृत की गई है। स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10.11.1986 के आलोक में अहाता नम्बर 140 की पत्रावली संख्या 77 अनवानी हरभजन कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी. का गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें प्रकरण की प्रशासनिक जांच कर्ता पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा निम्न आक्षेप लाल स्याही से अंकित किए गए हैं:-

1. विक्री पुष्टि के लिए सक्षम अधिकारी के पास नहीं भेजी गई। (नियम 265)
2. प्रस्तुत नक्शा पर नक्शा नवीस तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। (नियम 257(5))
3. जारी नोटिस दोनो को चस्पा नहीं किया गया। (नियम 260)
4. निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.1983 में प्रार्थी द्वारा कोई अहाता नम्बर की मांग नहीं की गई है। किस आधार पर इसे अहाता नम्बर 140 दिया गया ? (नियम 256)
5. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है। (नियम 260(2))
- 6.

राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत आबादी भूमि के विक्रय की संपूर्ण प्रक्रिया राज0 पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से 265 में विहित की गई है। निगरानीधीन पट्टे की पत्रावली में उक्त प्रक्रिया को नहीं अपनाए जाने से उपरोक्त आक्षेपों लगाए गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं हुई है। नियमों में विहित प्रावधानों और प्रक्रिया की पालना नहीं होने के कारण पट्टो की वैद्यता नहीं रही। लिहाजा इन्हें निरस्त करने के आदेश सक्षम स्तर से दिए गए थे। जिसकी पालना में उक्त अहातो के पट्टे तत्समय निरस्त कर दिये गए। इस आदेश के विरुद्ध निगरानीकार द्वारा कोई चाराजोही किया जाना अभिलेख पर नहीं पाया गया है।



निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को आवंटित अहातों के सम्बन्ध में किये गए आक्षेपों के बारे में रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर परीक्षण किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से प्रस्तुत अभिलेख पत्रावली संख्या 48 गेजसिंह, सुरेन्द्र सिंह 37 आर.बी. बाबत खरीदने अहाता संख्या 140-143-144 को देखने में स्पष्ट होता है कि इसमें विक्रय प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टा नम्बर 86 दिनांक 05.04.1991 जारी किया गया है जो अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की मांग व आवेदन पर बाद सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 20.03.1991 से जारी हुआ है। नीलामी की सूचना एवं फर्द नीलामी की कार्यवाही की भी इसमें पुष्टि होती है। यह 1500/-रुपये जरिये रसीद नम्बर 88 दिनांक 20.03.1991 की उच्चतम बोली पर दिया गया है। इस विक्रय पर बाद में पट्टा जारी होने तक कोई आक्षेप भी प्रस्तुत होना नहीं पाया गया है। और न ही यह पट्टा निरस्त हुआ है अतः यह पट्टा आज भी प्रभाव में है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता का आक्षेप ग्राह्य नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. को बाद प्रशासनिक जांच एवं पं.समिति पदमपुर के द्वारा

/s/

श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विक्रय की पुष्टि नहीं किये जाने एवं जांच में विक्रय प्रक्रिया को आक्षेपित कर लिये गए निर्णय के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर द्वारा प्रदत्त आदेशों के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर प्रस्ताव 138 दिनांक 10.11.1986 जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण के पट्टों को, जो कि अहाता संख्या 140 चक 37 आर.बी. को सार्वजनिक नोटिस दिनांक 15.11.1986 चरखांदगी (नियम 259(2) की पालना में) के पश्चात निरस्त करने का ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित किया गया वह विधिसम्मत है। अतः निगरानीकृत प्रस्ताव संख्या 138 दिनांक 10.11.1986 में हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत 3 आर.बी.ए. के प्रस्ताव संख्या 138 दिनांक 10.11.1986 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



28/5/18
(नखतदान बारहठ)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।
श्रीगंगानगर